रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-06062024-254592
CG-HR-E-06062024-254592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946
No. 395] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग,
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)
अधिसूचना

गुरुग्राम, 28 मई, 2024

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) (पाँचवां संशोधन) विनियम, 2024

जेईआरसी सं.-14/2010.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों और इस संबंध में आयोग को सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) मौजूदा जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 (जिसे आगे मूल विनियम कहा जाएगा) में संशोधन किया गया है।

विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और अनुप्रयोग की सीमा

(i) इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) (पाँचवां संशोधन), विनियम 2024 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(iii) ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के बाध्य इकाइयों पर लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन:

(i) विनियम 2 (एफ) में, "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2010" को "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022" के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ii) मूल विनियमों के विनियम 2 (i) के तहत प्रदान की गई फ्लोर प्राइस और फॉरबियरेंस प्राइस की परिभाषा को हटाया जाता है।

(iii) मूल विनियमों के विनियम 2 (i) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

(i1) हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन/अमोनिया के रूप में परिभाषित किया जाएगा; इसमें संग्रहित नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास से उत्पादित हाइड्रोजन/अमोनिया शामिल हैं।

(iv) मूल विनियमों के विनियम 2(जे) के अनुसार एचपीओ की परिभाषा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

(जे) हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशन (एचपीओ) का तात्पर्य 31 मार्च 2024 के बाद शुरू की गई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स (पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (पीएसपी) और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स (एसएचपी) सहित) से बिजली खरीदने की बाध्यता से है।

(v) मूल विनियमों के विनियम 2(एम) के तहत प्रदान की गई एलएचपी की परिभाषा को हटा दिया जाएगा।

(vi) मूल विनियमों के विनियम 2(पी) के अनुसार बाध्य इकाई की परिभाषा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

(पी) बाध्य इकाई का मतलब उन इकाइयों से है जिन्हें अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ई) के तहत नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसमें वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता शामिल हैं।

(vii) मूल विनियमों के विनियम 2 (टी) के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाता है:

(टी1) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का अर्थ एक ऐसे उत्पादन केंद्र से है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन करता है।

(टी2) भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का तात्पर्य है भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का संयोजन या एक ही अंतर-संयोजन बिंदु पर भंडारण के साथ नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना का संयोजन।

(टी3) नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना का तात्पर्य एक ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से है जो एक ही अंतर-संयोजन बिंदु पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संयोजन से बिजली का उत्पादन करती है।

(टी4) भंडारण का अर्थ है ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जिसमें ठोस बैटरी, प्रवाह बैटरी, पंप भंडारण, संपीड़ित वायु, ईंधन सेल, हाइड्रोजन भंडारण या किसी अन्य तकनीक जैसी विधियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को संग्रहीत किया जाता है तथा संग्रहीत ऊर्जा को बिजली के रूप में वितरित किया जाता है।

(viii) मूल विनियमों के विनियम 2(डब्ल्यू) के पश्चात निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

(एक्स) पवन आरपीओ का अर्थ है 31 मार्च 2024 के बाद शुरु की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से बिजली की खरीद की बाध्यता से है।

(वाई) अन्य आरपीओ का अर्थ एचपीओ और पवन आरपीओ के अलावा किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना से बिजली की खरीद की बाध्यता से है और इसमें 1 अप्रैल, 2024 से पहले शुरु की गई सभी डब्ल्यूपीपी और हाइड्रो पावर परियोजनाओं [पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) और लघु हाइड्रो परियोजनाओं (एसएचपी) सहित] से प्राप्त ऊर्जा शामिल होगी, जिसमें मुफ्त बिजली भी शामिल होगी।

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन:

(i) मूल विनियमों के विनियम 3.1 के तहत सूची 1(ए) को नीचे दी गई तालिका से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

सूची 1(ए)

कुल खपत होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (kWh) से प्रतिशत (%) में नवीकरणीय खरीद की बाध्यता न्यूनतम मात्रा					
वित्तीय वर्ष	**पवन नवीकरणीय ऊर्जा (पवन आरपीओ)**	**जल नवीकरणीय ऊर्जा (एचपीओ)**	**वितरित नवीकरणीय ऊर्जा आरपीओ**	**अन्य नवीकरणीय ऊर्जा (अन्य आरपीओ)**	**कुल आरपीओ (%)**
2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.35%	29.91%
2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	41.36%
2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

(ii) मूल विनियम के विनियम 3.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

आरपीओ की गणना ऊर्जा के संदर्भ में बिजली की कुल ऊर्जा खपत के हिस्से के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।

(iii) मूल विनियम का विनियम 3.3 हटाया जाता है।

(iv) मूल विनियम के विनियम 3.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(3.4) अन्य आरपीओ को विनियम 2(जे), 2(एक्स) और 3.11 में निर्दिष्ट के अलावा किसी भी नवीकरणीय स्रोत से पूरा किया जा सकता है और इसमें 1 अप्रैल, 2024 से पहले शुरु की गई सभी पवन और परियोजनाओं और हाइड्रो पावर परियोजनाओं [पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) और लघु हाइड्रो परियोजनाओं (एसएचपी) सहित] से प्राप्त ऊर्जा शामिल होगी, जिसमें मुफ्त बिजली भी शामिल होगी।

किसी विशेष वर्ष में निर्धारित पवन ऊर्जा आरपीओ की प्राप्ति में किसी कमी को एचपीओ से पूरा किया जा सकेगा जो उस वर्ष के ऊर्जा घटक से अधिक या विपरित है।

किसी विशेष वर्ष में पवन आरपीओ या एचपीओ घटक के तहत शेष अतिरिक्त ऊर्जा खपत को अन्य आरपीओ के हिस्से के रूप में माना जा सकता है।

किसी विशेष वर्ष में अन्य आरपीओ के अंतर्गत किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा खपत का उपयोग निर्धारित पवन आरपीओ या एचपीओ की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

(v) मूल विनियम के विनियम 3.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

(3.5) प्रत्येक बाध्य इकाई अपने स्वयं के उत्पादन के माध्यम से या अन्य स्रोतों/लाइसेंसधारियों से खरीद के माध्यम से या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की खरीद के माध्यम से या उपरोक्त विकल्पों में से किसी के संयोजन के माध्यम से अपने आरपीओ लक्ष्य को पूरा करेगी। कोई भी दीर्घकालिक खरीद व्यवस्था केवल आयोग की मंजूरी से की जाएगी। आयोग मामले-दर-मामले के आधार पर दीर्घकालिक पीपीए को मंजूरी देगा।

(vi) मूल विनियमन के विनियमन 3.6 को हटाया जाता है।

(vii) मूल विनियम के विनियम 3.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

(3.7) एचपीओ की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के बाद शुरु की गई जल विद्युत परियोजनाओं से संघ शासित

प्रदेश/राज्य को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क बिजली से भी की जा सकती है।

बशर्ते कि हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा घटक को केंद्र सरकार द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर अनुमोदित भारत के बाहर स्थित हाइड्रो पावर परियोजनाओं से भी पूरा किया जा सकता है।

(viii) मूल विनियमों के विनियम 3.8 में, 'गैर-सौर हाइड्रो नवीकरणीय पर्चेज ऑब्लिगेशन शब्द को "हाइड्रो पर्चेज ऑब्लिगेशन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) मूल विनियमों के विनियम 3.10 में, 'एचपीओ' शब्द को "आरपीओ" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

(x) मूल विनियम के विनियम 3.10 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

(3.11) वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक (वितरित नवीकरणीय ऊर्जा आरपीओ) की पूर्ति केवल उन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न ऊर्जा से की जाएगी, जिनका आकार 10 मेगावाट से कम है और इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी विन्यासों (नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, मीटर के पीछे के प्रतिष्ठान और कोई अन्य विन्यास) के अंतर्गत सौर प्रतिष्ठान शामिल होंगे:

बशर्ते कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अनुपालन को सामान्यतः ऊर्जा (kWh) के संदर्भ में माना जाएगा:

आगे यह भी है कि यदि बाध्य उपभोक्ता वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध उत्पादन डेटा प्रदान करने में असमर्थ है, तो रिपोर्ट की गई क्षमता को ऊर्जा के संदर्भ में 3.5 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति दिन (kWh/kW/day) के गुणक द्वारा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जाएगा।

(3.12) कोई भी संस्था, चाहे बाध्य हो या न हो, निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, खरीद और उपभोग करने का विकल्प चुन सकती है:

क नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्वयं उत्पादन: संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई क्षमता सीमित नहीं होगी और ऐसे संयंत्र भारत में किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं और स्वतंत्र स्रोत का उपयोग करके विद्युत का संचरण किया जाएगा:

बशर्ते कि उत्पादन संयंत्र इकाई द्वारा स्वयं या किसी डेवलपर द्वारा स्थापित किया जा सकता है जिसके साथ इकाई ने विद्युत खरीद संबंधी करार किया हो।

ख वितरण लाइसेंसधारी के अनुरोध द्वारा:

वितरण लाइसेंसधारी से या वितरण लाइसेंसधारी के अलावा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीदी गई हरित ऊर्जा, जो कि बाध्य इकाई के नवीकरणीय बाध्यता की खरीद से अधिक है, जिसे वितरण लाइसेंसधारी के नवीकरणीय बाध्य खरीद अनुपालन के लिए गिना जाएगा।

ग केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की खरीद से।

घ ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की खरीद: बाध्य इकाई ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया खरीदकर भी अपने नवीकरणीय खरीद बाध्यता को पूरा कर सकती है और ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की मात्रा की गणना नवीकरणीय स्रोतों से एक मेगावाट बिजली या इसके गुणकों से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की समानता पर विचार करके की जाएगी और इस संबंध में मानदंड केंद्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाएगा। ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की खरीद को अन्य आरपीओ में गिना जाएगा।

ङ कोई अन्य स्रोत जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(3.13) हरित प्रमाणपत्र: वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं के नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व से परे उपभोक्ता के अनुरोध पर वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा आपूर्ति की गई हरित ऊर्जा के लिए उपभोक्ताओं को वार्षिक आधार पर "हरित प्रमाणपत्र" प्रदान किया जाता है।

4. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन:

(i) विनियमन 4.1 में, "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने हेतु नियम और शर्तें) विनियम 2010" को "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु नियम और शर्तें) विनियम, 2022" के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ii) मूल विनियम के विनियम 4.1 के बाद का प्रावधान हटा दिया जाएगा।

(iii) विनियमन 4.2 में, "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2010" को "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022" के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन:

विनियम 5.2 में, "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2010" को "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022" के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।

6. मूल विनियमों के विनियम 7 में संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 7.2 के बाद निम्नलिखित विनियम को शामिल किया जाता है:

7.3 बाध्य इकाई जो कि स्वतंत्र स्त्रोत उपभोक्ता हैं या कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ता हैं, उन्हें गैर-जीवाश्म ईंधन स्त्रोत पर ध्यान दिए बिना निर्दिष्ट कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुसार अपने दायित्व को पूरा करना होगा।

7. मूल विनियमों के विनियम 8 में संशोधन:

(i) मूल विनियमों का विनियम 8.1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

परिचालन अवधि के दौरान शूरु की गई नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का मूल्य निर्धारण या तो टैरिफ मूल्य निर्धारण संरचना के अनुसार होगा, जैसा कि आयोग के प्रासंगिक प्रौद्योगिकी विशिष्ट टैरिफ विनियमों (आयोग द्वारा निर्धारित परियोजना विशिष्ट टैरिफ सहित) में निर्धारित किया जा सकता है या सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार आरईसी तंत्र के अनुसार या अधिनियम की धारा 63 के तहत अपनाए गए टैरिफ के अनुसार होगा।

(ii) मूल विनियमों से विनियम 8.3 को हटाया जाता है।

(iii) मूल विनियमों के विनियम 8.3 के बाद निम्नलिखित विनियम को शामिल किया जाता है:

8.4 क्रॉस-सब्सिडी अधिभार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार होगा:

बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र से हरित ऊर्जा खरीदने वाले ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता के लिए क्रॉस सब्सिडी अधिभार, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र के संचालन की तिथि से बारह वर्षों के दौरान, उस वर्ष के लिए निर्धारित अधिभार के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा जिसमें स्वतंत्र स्त्रोत प्रदान की गई है;

बशर्ते कि अतिरिक्त अधिभार ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं होगा, यदि ऐसे उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा रहा है:

बशर्ते कि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने की स्थिति में क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि अतिरिक्त अधिभार उन अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के मामले में लागू नहीं होगा जो दिसंबर, 2032 तक लागू किया जाएगा और ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति की जाएगी।

बशर्ते कि यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

(iv) मूल विनियमों के विनियम 8 के तहत प्रदान किए गए (नोट 3) को हटाया जाता है।

8. मूल विनियमों के विनियम 10 में संशोधन:

(i) मूल विनियमों के विनियम 10 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

यदि बाध्य इकाई किसी वर्ष के दौरान इन विनियमों में दिए गए नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा नहीं करती है और प्रमाणपत्र भी नहीं खरीदती है, तो आयोग बाध्य इकाई को राज्य एजेंसी द्वारा बनाए और बनाए रखे जाने वाले एक अलग कोष में उतनी राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है, जितनी कि आयोग आरपीओ में कमी की मात्रा के लिए प्रासंगिक वर्ष के लिए पावर एक्सचेंज में खोजे गए भारित औसत आरईसी मूल्य पर निर्धारित किया गया है। जहां कोई भी बाध्य इकाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीद की अपेक्षित न्यूनतम मात्रा खरीदने या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करने या आयोग द्वारा तय किए गए अनुसार एक अलग निधि में जमा करने के दायित्व का पालन करने में विफल रहती है, तो वह अधिनियम की धारा 142 के तहत आयोग द्वारा तय किए गए दंड के लिए भी उत्तरदायी होगी।

(ii) विनियम 10.1 से 10.4 वही रहेगा जो मूल विनियम में दिया गया है।

एस.डी.शर्मा, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./172/2024-25]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 28th May, 2024

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Procurement of Renewable Energy) (Fifth Amendment) Regulations, 2024

No. JERC-14/2010.—In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling the Commission in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories) hereby amend its existing JERC (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the Principal Regulations).

REGULATIONS

1. Short title, commencement, and extent of application

(i) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Procurement of Renewable Energy) (Fifth Amendment), Regulations 2024.

(ii) These Regulations shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(iii) These Regulations shall extend and apply to the obligated entities in the entire of the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.

2. Amendment in Regulation 2 of the Principal Regulations:

(i) In Regulation 2 (f), "Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations 2010" shall be substituted with "Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022".

(ii) The definition of Floor Price and Forbearance Price as provided under Regulation 2 (i) of the Principal Regulations shall be omitted.

(iii) The following shall be inserted after Regulation 2 (i) of the Principal Regulations:

(i1) Green Hydrogen/Green Ammonia shall be defined as Hydrogen/Ammonia produced by way of electrolysis of water using Renewable Energy; including Renewable Energy which has been banked and the Hydrogen/Ammonia produced from biomass.

(iv) The definition of HPO as per Regulation 2(j) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

(j) Hydro Purchase Obligation (HPO) means obligation to procure power from Hydro Power Projects (including Pumped Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)) commissioned after 31.03.2024.

(v) The definition of LHP as provided under Regulation 2(m) of the Principal Regulations shall be omitted.

(vi) The definition of Obligated Entity as per Regulation 2(p) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

(p) Obligated Entity means the entities which are mandated under clause (e) of Sub-section (1) of Section 86 of the Act to fulfil renewable purchase obligation, which includes Distribution Licensee, Captive User and Open Access Consumer.

(vii) Following shall be inserted after Regulation 2 (t) of the Principal Regulations:

(t1) Renewable Energy Project means a generating station that produces electricity from renewable energy sources.

(t2) Renewable Energy with Storage Project means a combination of renewable energy project with storage or a combination of renewable hybrid energy project with storage at the same inter-connection point.

(t3) Renewable Hybrid Energy Project means a renewable energy project that produces electricity from a combination of renewable energy sources, connected at the same inter-connection point.

(t4) Storage means energy storage system utilizing methods and technologies like, solid state batteries, flow batteries, pumped storage, compressed air, fuel cells, hydrogen storage or any other technology, to store various forms of energy and to deliver the stored energy in the form of electricity.

(viii) The following shall be inserted after 2(w) of the Principal Regulations:

(x) Wind RPO means obligation to procure power from the Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31st March 2024.

(y) Other RPO means obligation to procure power from any renewable energy power project other than HPO and Wind RPO and shall comprise energy from all WPPs and Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], including free power, commissioned before the 1st April, 2024.

3. Amendment in Regulation 3 of the Principal Regulations:

(i) The Table 1(a) under Regulation 3.1 of the Principal Regulations shall be substituted with the Table provided below:

Table 1(a)

Minimum Quantum of Renewable Purchase Obligation (RPO) in percentage (%) from Renewable Energy Sources (in kWh) of total consumption					
Financial Year	**Wind renewable energy (Wind RPO)**	**Hydro renewable energy (HPO)**	**Distributed renewable energy RPO**	**Other renewable energy (Other RPO)**	**Total RPO (%)**
2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.35%	29.91%
2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	41.36%
2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

(ii) Regulation 3.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

RPO to be calculated in energy terms as a percentage of total share of energy consumption of electricity.

(iii) The Regulation 3.3 of the Principal Regulations shall be omitted.

(iv) Regulation 3.4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

(3.4) Other RPO may be met from any renewable source other than specified in Regulations 2(j), 2(x), and 3.11 and shall comprise energy from all WPPs and Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], including free power, commissioned before the 1st April, 2024.

Provided that any shortfall in achievement of stipulated Wind RPO in a particular year may be met with HPO which is in excess of that energy component for that year and vice-versa.

Provided further that the balance excess energy consumption under Wind RPO or HPO component in that year, may be considered as part of Other RPO.

Provided also that any excess energy consumption under Other RPO in a particular year, may be utilised to meet the shortfall in achievement of stipulated Wind RPO or HPO.

(v) Regulation 3.5 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

(3.5) Every obligated entity shall meet its RPO target by way of its own generation or by way of purchase from other sources / licensees or by way of purchase of Renewable Energy Certificates (RECs) in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 or by way of combination of any of the above options. Any long-term purchase arrangements shall be made only with the approval of the Commission. The Commission shall approve long term PPAs on case-to-case basis.

(vi) Regulation 3.6 of the Principal Regulations shall be omitted.

(vii) Regulation 3.7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

(3.7) HPO may also be met out of the free power being provided to the UT/State from the Hydro Power Projects commissioned after 31st March, 2024.

Provided that the hydro renewable energy component may also be met from Hydro Power Projects located outside India as approved by the Central Government on a case-to-case basis.

(viii) In Regulation 3.8 of the Principal Regulations, the word 'non-solar hydro renewable purchase obligations' shall be substituted by "hydro purchase obligations".

(ix) In Regulation 3.10 of the Principal Regulations, the word 'HPO' shall be substituted by "RPO".

(x) The following shall be inserted after Regulation 3.10 of the Principal Regulations:

(3.11) The distributed renewable energy component (Distributed renewable energy RPO) shall be met only from the energy generated from renewable energy projects that are less than 10 MW in size and shall include solar installations under all configurations (net metering, gross metering, virtual net metering, group net metering, behind the meter installations and any other configuration) notified by the Central Government:

Provided that the compliance against distributed renewable energy shall ordinarily be considered in terms of energy (Kilowatt hour units):

Provided further that in case the obligated consumer is unable to provide generation data against distributed renewable energy installations, the reported capacity shall be transformed into distributed renewable energy generation in terms of energy by a multiplier of 3.5 units per kilowatt per day (kWh/kW/day).

(3.12) Any entity, whether obligated or not may elect to generate, purchase and consume renewable energy as per their requirements by one or more of the following methods:

A. Own Generation from Renewable Energy Sources**:** There shall not be any capacity limit for installation of power plants from renewable energy sources, by entities for their own consumption and such plants may be set up at any location in India and power shall be transmitted by using open access:

Provided that the generating plant may be set up by the entity itself or by a developer with which the entity enters into a power purchase agreement.

B. By requisition from Distribution Licensee:

The green energy purchased from distribution licensee or from Renewable Energy sources other than distribution licensee in excess of Renewable Purchase Obligation of obligated entity shall be counted towards Renewable Purchase Obligation compliance of the distribution licensee.

C. By purchase of Renewable Energy Certificates (RECs) in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022.

D. Purchase of Green hydrogen or Green ammonia: The obligated entity can also meet their Renewable Purchase Obligation by purchasing green hydrogen or green ammonia and the quantum of such green hydrogen or green ammonia would be computed by considering the equivalence to the green hydrogen or green ammonia produced from one MWh of electricity from the renewable sources or its multiples and norms in this regard shall be notified by the Central Commission. The purchase of such green hydrogen or green ammonia shall be counted towards Other RPO.

E. Any other sources, as may be, determined by the Central Government.

(3.13) Green certificate: The Distribution Licensee shall give "Green Certificate" on yearly basis to the consumers for the green energy supplied by the distribution licensees to consumer on his request beyond the renewable energy obligation of the consumers.

4. Amendment in Regulation 4 of the Principal Regulations:

(i) In Regulation 4.1, "Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewal Energy Generation) Regulations 2010" shall be substituted with "Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022".

(ii) The proviso after Regulation 4.1 of the Principal Regulations shall be deleted.

(iii) In Regulation 4.2, "Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewal Energy Generation) Regulations 2010" shall be substituted with "Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022".

5. Amendment in Regulation 5 of the Principal Regulations:

In Regulation 5.2, "Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewal Energy Generation) Regulations 2010" shall be substituted with "Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022".

6. Amendment in Regulation 7 of the Principal Regulations:

Following Regulation shall be inserted after Regulation 7.2 of the Principal Regulations:

7.3 The obligated entity who are open access consumers or consumers with Captive Power Plants shall fulfil their obligation as per the specified total renewable energy target irrespective of the non-fossil fuel source.

7. Amendment in Regulation 8 of the Principal Regulations:

(i) Regulation 8.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

The pricing of new renewable energy projects commissioned during the operative period shall be as per either the tariff pricing structure, as may be stipulated in the relevant technology specific tariff Regulations of the Commission (including project specific tariff decided by the Commission) or as per the REC mechanism followed in accordance with the CERC (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 or as per the tariff adopted under Section 63 of the Act.

(ii) Regulation 8.3 of the Principal Regulations shall be omitted.

(iii) Following Regulation shall be inserted after Regulation 8.3 of the Principal Regulations:

8.4 The Cross-subsidy surcharge shall be as per the provisions of tariff policy notified by the Central Government under the Act:

Provided that the cross-subsidy surcharge for Green Energy Open Access Consumer purchasing green energy, from a generating plant using renewable energy sources, shall not be increased, during twelve years from the date of operating of the generating plant using renewable energy sources, by more than fifty percent of the surcharge fixed for the year in which open access is granted;

Provided further that the additional surcharge shall not be applicable for Green Energy Open Access Consumers, if fixed charges are being paid by such a consumer:

Provided also that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable in case power produced from a Waste-to-Energy plant is supplied to the Open Access Consumer.

Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case electricity produced from offshore wind projects, which are commissioned up to December, 2032 and supplied to the Open Access Consumer.

Provided also that Cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

(iv) Note-3 provided under Regulation 8 of the Principal Regulations shall be omitted.

8. Amendment in Regulation 10 of the Principal Regulations:

(i) Regulation 10 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

If the obligated entity does not fulfill the renewable purchase obligation as provided in these Regulations during any year and also does not purchase the certificates, the Commission may direct the obligated entity to deposit into a separate fund, to be created and maintained by State Agency, such amount as the Commission may determine at the weighted average REC price discovered at Power Exchange for the relevant year, for quantum of shortfall in RPO. Where any obligated entity fails either to comply with the obligation to purchase the required minimum quantum of purchase from renewable energy sources or procure the Renewable Energy Certificate (s) or deposited into a separate fund as decided by the Commission, it shall also be liable for penalty as may be decided by the Commission under Section 142 of the Act.

(ii) The proviso 10.1 to 10.4 shall remain same as provided in the Principal Regulations.

S.D.SHARMA, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./172/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.06.06 22:03:29 +05'30'